मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति, परम पूज्य तुलछाराम महाराज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भेंट कर उनका स्नेहाशीष प्राप्त किया।

ईरान ने की जवाबी कार्यवाही, तेल अवीव के कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया

इज़रायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी, मिसाइलें दागना बंद नहीं किया तो ''तेहरान जलेगा''

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। यरुशलम द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए अनायास और अनुचित मिसाइल हमलों से भड़के ईरान ने शुक्रवार रात को तेहरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल अड्डों पर इज़राइली हमलों के जवाब में इज़राइल पर भारी मिसाइल हमला किया, जिससे तेल अवीव में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचा है।

दोनों देश एक तीव्र संघर्ष में उलझ चुके हैं, जो दुनिया को वैश्विक युद्ध की ओर धकेल सकता है। इज़राइल का यह दावा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है, निराधार प्रतीत होता है, जैसा कि अमेरिका ने इराक के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जो अंततः पूरी तरह गलत साबित हुआ।

विशेषज्ञों ने कहा, इसी रणनीति को दोहराते हुए, ट्रम्प प्रशासन के समर्थन से इज़राइल मीडिया में जोर-शोर से ऐसा प्रचार कर रहा है, ताकि ईरान पर हमलों को उचित ठहराया जा सके, तेहरान ने लगातार यह कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी तरह के परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

ईरान के शुक्रवार रात और शनिवार तड़के किए गए जवाबी हमलों से पहले, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई ने टेलिविज़न पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ज़ायनिस्ट शासन को ''कड़ी सज़ा'' देने की बात कही थी।

इज़राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज़ ने तत्काल खामेनेई को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इज़राइली नागरिकों पर मिसाइलें दागनी जारी रखीं, तो ''तेहरान जल जाएगा''।

कात्ज़ ने एक बयान में कहा, ''ईरानी तानाशाह ईरानी नागरिकों को बंधक बना रहा है और उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला रहा है, जिसमें वे, खासकर तेहरान के निवासी, इज़राइली नागरिकों को पहुँचे नुकसान की बड़ी कीमत चुकाएंगे। अगर खामेनेई ने इज़राइली इलाकों पर मिसाइलें दागनी जारी रखीं, तो तेहरान जलकर राख हो जाएगा''।

इस बीच, ईरानी हमले जारी रहने वाले हैं, और ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी ने शनिवार को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि आने वाले दिनों में, इस क्षेत्र में स्थितअमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा।

- **दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है, रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहा, यह स्थिति दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर ले जा सकती है।**
- **ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस को चेतावनी दी, अगर उन्होंने इज़रायल की मदद की तो ईरान उनके अड्डों व जहाजों को निशाना बनाएगा।**

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से, फ़ार्स ने रिपोर्ट किया, ''यह टकराव बीती रात की सीमित कार्रवाई पर समाप्त नहीं होगा। ईरानी हमले जारी रहेंगे और आक्रांताओं के लिए यह काफ़ी दुखदायी और पश्चातापजनक होगा''।

अधिकारियों ने कहा कि यह युद्ध आने वाले दिनों में इस (इज़राइली) शासन द्वारा क़ब्ज़ा किए गए सभी क्षेत्रों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी अड्डों तक फैल जाएगा।

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने ईरान के इज़राइल पर हमलों को रोकने में मदद की, तो उनके अड्डों और जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा।

इज़राइल में हवाई हमले के सायरन पूरे देश में, विशेष रूप से तेल अवीव और यरुशलम में बजे, जिससे नागरिकों को बंकरों की ओर भागना पड़ा, क्योंकि ईरानी मिसाइलों की लगातार बारिश हुई और इज़राइली अवरोधक उन्हें रोकने के लिए सक्रिय हो गए।

इज़राइल की एम्बुलेंस सेवा के अनुसार, एक पुरुष और एक महिला की उस समय मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जब एक मिसाइल उनके घर के पास गिरी।

तेल अवीव के बाहर के शहर ऋशोन लेजिओन में ध्वस्त हुए अपार्टमेंट भवनों के मलबे में बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं।

फ़िलिस्तीनी रेड क्रेसेंट के अनुसार, ईरान समर्थित हूती मिलिशिया द्वारा यमन से दागी गई एक मिसाइल ने इज़राइल-आधिकृत वेस्ट बैंक में पाँच फ़िलिस्तीनियों, जिनमें तीन बच्चे शामिल थे, की जान ले ली।

तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया, तेहरान में शुक्रवार रात कई विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं।

ईरानी मीडिया ने बताया, ईरानी सशस्त्र बलों के दो उप-सेनापतियों की मौत इज़राइली हमलों में हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन उनकी मौत की जानकारी शनिवार को दी गई।

फ़ार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर दो मिसाइलें गिरीं, और ईरानी मीडिया ने वहाँ आग लगने की खबरें दीं। यह एयरपोर्ट ईरान के शीर्ष नेतृत्व के निकट स्थित है और वहां एक वायुसेना अड्डा भी है, जिसमें लड़ाकू और परिवहन विमान तैनात हैं।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि इज़राइली हमलों में 78 लोग मारे गए, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं, और 320 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें अधिकांश नागरिक हैं।

दो अमेरिकन अधिकारियों ने बताया, अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को इज़राइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। इज़राइल की सेना ने कहा कि ईरान ने शुक्रवार को 100 से कम मिसाइलें दागीं, जिनमें से अधिकांश को रोक लिया गया या वे लक्ष्य से चूक गईं।

दिनभर चले इज़राइली हमलों और उसके जवाब में हुई ईरानी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ा दी है, हालाँकि ईरान के सहयोगी ग़ाज़ा में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह पहले ही इज़राइल के हमलों में कमजोर हो चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रोसी ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि नतांज़ का पायलट परिशोधन केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फ़ोर्दो और इस्फ़हान में दो अन्य ठिकानों पर हुए इज़राइली हमलों की जानकारी अब भी एकत्र की जा रही है।

कांग्रेस में जातिगत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जातियों की पहचान को लेकर विवाद हो सकते हैं।

कुछ कांग्रेस नेताओं को यह भी चिंता है कि यह प्रक्रिया बाँटने वाली तथा जटिल हो सकती है तथा इसमें गलतियों की काफी संभावनाएँ हैं। कुल मिलाकर, यह समाज में नए तनाव पैदा कर सकती है।

भारत में आखिरी बार जातिगत आंकड़े 1931 में एकत्रित किए गए थे।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) करवाई थी, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए, क्योंकि इनमें विसंगतियाँ बताई गई थीं।

किन्तु आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस उस समय राजनीतिक जोखिम से बचना चाहती थी, क्योंकि ये आंकड़े आरक्षण नीति और सामाजिक समीकरणों को बदल सकते थे।

हालिया वर्षों में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना का समर्थन खुलकर करना शुरू इसलिये किया है, क्योंकि वे सामाजिक न्याय और संसाधनों के पुनर्वितरण पर जोर देना चाहते हैं।

लेकिन पार्टी के भीतर विरोध की प्रमुख वजहें हैं जैसे, राजनीतिक समीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण का डर, पारंपरिक वोट बैंक के दूर छिटक जाने की चिंता, इस मुद्दे पर ऐतिहासिक अनिर्णय।

विशेष रूप से भाजपा की ओबीसी वर्ग में बढ़ती पहुंच और क्षेत्रीय सहयोगी दलों के दबाव के मद्देनज़र, कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपना रुख अधिक स्पष्ट करती दिख रही है।

कोमा में गया कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक नियमित वेतन का अधिकारी

जयपुर, 14 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारी के कोमा में जाने पर उसे सेवानिवृति तक नियमित वेतन का अधिकारी माना है। अदालत ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कहा है कि वह मेडिकल टीम के जरिए कर्मचारी की दिव्यांगता की जांच दो सप्ताह में पूरी करे तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्णय ले। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश कर्मचारी लक्ष्मण सेन की पत्नी गुड़िया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति जेवीवीएनएल में तकनीकी सहायक हैं। एक दुर्घटना में घायल होकर वे कोमा में चले गए। इसके बाद बिजली कंपनी ने उनका वेतन बंद कर दिया, जबकि दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी दिव्यांग हो जाए तो उसे उसकी सेवानिवृति की उम्र तक नियमित वेतन दिया जाएगा। ऐसे में बिजली कंपनी को निर्देश दिए जाएं कि वह याचिकाकर्ता के पति का नियमित वेतन जारी करें।

- **हाई कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम को दो सप्ताह में दिव्यांगता की जाँच करे व दिव्यांगता अधिनियम के तहत निर्णय ले।**

इसके जवाब में बिजली कंपनी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति की ओर से दिव्यांगता को लेकर कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें नियमित वेतन का लाभ नहीं दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बिजली कंपनी को दो सप्ताह में याचिकाकर्ता के पति की मेडिकल जांच कर रिपोर्ट के आधार पर धारा 20 के तहत आगामी कार्रवाई करने को कहा है।

राजस्थान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिसंचरण तंत्र सक्रिय है तथा एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी है। इससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 14 जून से प्रदेश के कई जिलों-जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर व भरतपुर-में बादल, तेज़ आंधी (50-60 किमी/घंटा), बिजली की गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं।

इन बदलावों के चलते अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 20 जून के बाद प्रदेश में मानसून की बारिश की तीव्रता और विस्तार में बढ़ोतरी होगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मानसून समय पर और पूरी सक्रियता के साथ आता है, तो यह कृषि क्षेत्र के लिए बेहद शुभ संकेत होगा। इससे जल स्तर में सुधार और खेतों की बुवाई में तेजी आ सकेगी।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित

केन्द्र सरकार ने इस 11 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की जो तीन माह में रिपोर्ट देगी

नयी दिल्ली, 14 जून। सरकार ने अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान की गुरुवार को हुई दुर्घटना की समग्रता से जांच के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस दुर्घटना को लेकर हर तरह के सवाल का जवाब तलाशेगी और तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने शनिवार को यहां उड़ान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी और यह भी बताया कि विमान का डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया और उसकी डिकोडिंग की जा रही है। नायडू ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि वे इस दुर्घटना के शिकार यात्रियों के परिजनों के दर्द को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने पिता को एक दुर्घटना में खोया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने के तीन घंटे बाद जब वे अहमदाबाद में घटनास्थल पर पहुंचे तो गुजरात सरकार की एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में लगे थे। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) ने अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इस जांच से उत्तर मिलेगा कि तकनीकी स्तर पर क्या कमी या चूक हुई थी।

नायडू ने कहा, पिछले दो दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद हवाईअड्डे के पास हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं... मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया, ताकि देख सकूँ कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए और यही रवैया गुजरात सरकार का भी था। भारत सरकार और मंत्रालय के अन्य लोगों का भी यही रवैया था। जब हम घटनास्थल पर पहुँचे, तो हमने देखा कि सभी संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया टीमें ज़मीन पर काम कर रही थीं, जो भी संभव हो, बचाव करने की कोशिश कर रही थीं, आग को कम करने और मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थीं, ताकि शवों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जा सके। विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं की जाँच करने के लिए बनाया गया था, को तुरंत सक्रिय किया गया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के माध्यम से चल रही तकनीकी जांच से एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कल शाम 5 बजे के आसपास घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है।

आरोपी पति को भारत डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की गई

जयपुर, 14 जून। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, महानगर द्वितीय ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने से जुड़े मामले में पासपोर्ट कार्यालय से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पीठासीन अधिकारी कंचन सिंह राजावत ने पासपोर्ट अधिकारी से 4 अगस्त तक यह रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि उन्होंने एक अक्टूबर 2024 के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की और आरोपी को भारत डिपोर्ट कराने के लिए क्या प्रयास किए। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना में आरोपी का पासपोर्ट और वीजा निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पत्नी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

- **पीठासीन अधिकारी ने पासपोर्ट अधिकारी को 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा।**

पत्नी के अधिवक्ता वाईके गुप्ता ने बताया कि अदालत ने गत एक अक्टूबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासपोर्ट, जयपुर को निर्देश दिया था कि वे सेन्ट्रल अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए आरोपी पति को कोर्ट में पेशी का निर्देश दें। यदि वह स्वयं के खर्चे पर एक महीने में पेश नहीं हो तो उसके पासपोर्ट-वीजा निरस्त कर उसे भारत डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालती आदेश के करीब सात माह बीतने के बावजूद, अब तक आदेश की पालना नहीं की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पत्नी ने पति के खिलाफ मई 2024 में पुलिस थाना महिला-उत्तर में दहेज प्रताड़ना व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आज विदेश यात्रा पर रवाना होंगे प्र.मंत्री मोदी

नयी दिल्ली, 14 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 से 18 जून के बीच कैनडा, साइप्रस और क्रोएशिया की यात्रा पर जाएंगे और कैनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि मोदी पहले चरण में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स के निमंत्रण पर 15-16 जून, 2025 को वहां की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यह पहली यात्रा होगी। मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून 16-17 को कनाडा के कनानैस्किस की यात्रा करेंगे। जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यह लगातार छठी भागीदारी होगी। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से एआई-ऊर्जा गठजोड़ और क्वांटम से संबंधित मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर जी-7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

- **प्र.मंत्री 15 से 18 जून के विदेश दौरे में पहले तो सायप्रस जाएंगे फिर कैनडा जाएंगे, जी-7 मीटिंग के लिए तथा अंत में क्रोएशिया जाएंगे।**

मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक के निमंत्रण पर 18 जून को वहां की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

राजस्थान का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुल 23 लाख 33 हजार 162 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 13 लाख 15 हजार 853 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

इस वर्ष अनारक्षित श्रेणी के 689366, अनुसूचित जाति के 333646, अनुसूचित जनजाति के 150224, अन्य पिछड़ा वर्ग के 948507, ईडब्लूएस के 154326 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों की संख्या 965996 और छात्राओं की संख्या 1310062 रही। इस वर्ष की परीक्षा में 939 विदेशी अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 11 उभयलिंगी (थर्ड जेंडर) शामिल हुए।

राहुल गांधी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिक बेरोजगार युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपेंगी। उन्होंने कहा कि बढ़ ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ ती और नशे की लत मानसिक अवसाद को देखते हुये उन्हें इससे मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट, एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिन्द्रा, एमेज़ॉन, जेप्टो, टाटा, सैमसंग, हीरो, बजाज, वोल्टास, जस्ट डायल, वोडाफोन, ब्लिंकिट और रेडिसन जैसी प्रमुख कंपनियां उन लगभग 100 कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने बेरोजगारों की सीधी भर्ती के लिए मैगा जॉब फेयर में भाग लेने पर सहमति जतायी है।

सीज़फायर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तबादला जैसलमेर किया था। अपील में कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया है और तनाव के हालात समाप्त हो गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने आपदा प्रबंधन के तहत अपने कर्मचारियों के किए गए ट्रांसफर वापस ले लिए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का तबादला निरस्त कर उसे उसके गृह जिले में नियुक्त किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग को पूर्व में किए तबादला- आदेश पर नए सिरे से विचार करने को कहा है।

17 जून से कश्मीर के पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे

श्रीनगर, 14 जून। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी मंगलवार, यानि 17 जून से राज्य के कई पर्यटन स्थलों और उद्यानों को जनता के लिए पुनः खोलने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा कि अन्य पर्यटन स्थलों को भी चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने कहा मैंने जम्मू एवं कश्मीर डिविजनों के उन कुछ पर्यटनस्थलों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है जिन्हें सुरक्षा कारणों से एहतियाती तौर पर अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दिया गया था। पहलगाम बाजार में बेताब घाटी एवं पार्क, वेरीनाग पार्क, कोकरनाग पार्क और अचहाबल पार्क 17 जून से पर्यटकों के लिये दोबारा खोल दिये जांएगे। उपराज्यपाल ने कहा दोबारा खुलने वाले अन्य पर्यटनस्थलों में श्रीनगर स्थित बादमवारी पार्क, डक पार्क, तकदीर पार्क, कठुआ में सार्थल धागर, रईसी में देवी पिंडी, सियाद बाबा एवं सूला पार्क, डोडा में गुलदंदा एवं जय घाटी और ऊधमपुर में पंछेरी शामिल है।

- **जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर यह जानकारी दी। ज्ञातव्य है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था।**

इज़रायल-ईरान युद्ध से खाड़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ - के इशारों पर चलने के मामले में इज़रायल का व्यवहार पाकिस्तान से अलग नहीं है। वह एक रणनीतिक कठपुतली बन गया है और उसकी एकतरफा कार्रवाहियाँ पूरे मध्य पूर्व को खतरे में डाल रही हैं। प्रो. पाशा ने यह भी कहा कि भारत सरकार को इस संकट के समय आगे आकर अपने इज़राइल और ईरान दोनों के साथ वर्षों पुराने संबंधों का उपयोग कर विवाद के कूटनीतिक समाधान की दिशा में पहल करनी चाहिए।

भारत, जिसने अब तक दोनों देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित रूप से बनाए रखा है, अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नई दिल्ली जहां एक ओर इज़राइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी साझेदारी रखता है, वहीं ईरान के साथ उसके सांस्कृतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध भी गहरे हैं। वर्षों से भारत ने ईरान में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे चाबहार बंदरगाह, में निवेश किया है, जो उसकी क्षेत्रीय संपर्क रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

- **प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा, जो जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर हैं, का कहना है कि इज़रायल ने पाकिस्तान की भांति, अमेरिका का ''स्टूज'' (पिछलग्गू) बनने का रास्ता अपनाया है तथा अमेरिका व यूरोपियन यूनियन के ''आदेशों'' की अनुपालना करने को तत्पर रहता है।**
- **प्रोफेसर पाशा की राय है, भारत के ईरान से गहरे सांस्कृतिक व इकोनॉमिक संबंध रहे हैं तथा अब इज़रायल से डिफैंस टैक्नॉलजी आधारित दोस्ती है। अतः भारत को अपनी इस अद्वितीय स्थिति को काम में लेते हुए दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति को शांत करने के लिए उपयोग करना चाहिए।**

यमन, सीरिया और इराक में पहले से ही जारी तनावों के बीच, खाड़ी क्षेत्र में किसी भी नई अस्थिरता का असर पूरे दक्षिण एशिया और उससे आगे तक महसूस किया जा सकता है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, भारत सहित कई देश पर्दे के पीछे शांति वार्ता और तनाव कम करने के प्रयासों में जुटे हैं, ताकि एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध को टाला जा सके।

जैसे-जैसे यह संकट गहराता जा रहा है, आने वाले दिन भारत की कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक सहनशक्ति और रणनीतिक दूरदर्शिता की कड़ी परीक्षा साबित होंगे, न केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए, बल्कि खाड़ी क्षेत्र से जुड़े लाखों जीवनों के लिए भी।

ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध होने के भय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद आर्थिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शुक्रवार को भारतीय रुपया वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि के प्रभाव में लगभग 0.6 प्रतिशत गिरा, जबकि शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यदि वर्तमान मूल्य स्तर बना रहा, तो घरेलू ईंधन की कीमतें 5 से 12 रूपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। यह पूरे आर्थिक ढांचे में असर डालेगा, जिससे परिवहन, पैकेजिंग, कृषि और रसायन जैसे क्षेत्रों में लागत बढ़ेगी। ये क्षेत्र, जो तेल पर आधारित कच्चे माल पर निर्भर हैं, मार्जिन पर दबाव का सामना करेंगे और निर्माता यह बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। महंगाई, जो हाल ही में नियंत्रण में आ रही थी, उसमें अचानक 0.5 से 1 प्रतिशत पॉइन्ट्स की बढ़ोतरी हो सकती है, यह इस पर निर्भर करेगा कि बढ़ते हुए तेल मूल्य कितने समय तक बने रहते हैं। नीति के स्तर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती की कोई भी योजना टालनी पड सकती है। वहीं वित्त मंत्रालय को ईंधन की कीमतों में तेज़ वृद्धि को रोकने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे उसकी आर्थिक गणना पर असर पड़ेगा। कमजोर होता रुपया डॉलर में तेल को और महंगा बना देगा, जिससे समस्या और जटिल हो जाएगी। हालाँकि भारत हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा है। देश ने अपने ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाने के लिए काम किया है, और अब वह रूस से रियायती दर पर तेल खरीद रहा है, अमेरिका से भी तेल ले रहा है और इराक तथा यूएई जैसे खाड़ी देशों पर अधिक निर्भर हो गया है। यदि कीमतें लंबे समय तक ऊँची बनी रहीं, तो रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हालांकि यह अंतिम उपाय होगा। घरेलू ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएँ भी भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सहनशक्ति का हिस्सा हैं, लेकिन ये तात्कालिक संकट का समाधान नहीं दे सकतीं।

- **भारत को ऑयल बॉण्ड, ऑयल पर लगी एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती आदि, सख्त कदम उठाने होंगे।**
- **पर, कितनी महँगाई बढ़ती है, आदि, आदि, इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान-इज़रायल युद्ध कितने दिन चलता है। पर, कटु सत्य है कि भारत का ''ग्रोथ मोमैन्टम'' तो पूर्णतया रूक जायेगा।**

अब आगे क्या होगा, यह संघर्ष की दिशा पर निर्भर करता है। यदि शत्रुता सीमित रहती है और इसका असर जहाजों के परिवहन या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता तो कच्चे तेल की कीमतें 75 से 80 डॉलर प्रति बैरल के बीच स्थिर हो सकती हैं, जो कष्टकारी तो है लेकिन इससे डील किया जा सकता है। मध्यम स्तर के बढ़ते संघर्ष के तहत, जिसमें बुनियादी ढांचे पर अप्रत्यक्ष हमले या क्षेत्रीय टैंकरों को खतरे शामिल हों तो तेल की कीमतें 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में, यदि होरमुज़ जलडमरूमध्य में पूरी तरह से नाकेबंदी या हमला होता है, कीमतें 120 डॉलर के पार जा सकती हैं, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में, महंगाई नाटकीय रूप से बढ़ेगी, रुपया गिरावट का सामना करेगा, और तथा केंद्र सरकार को प्रतिक्रियात्मक उपायों के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तेल बॉन्ड, उत्पाद शुल्क कटौती, और आयात विविधीकरण जैसी नीतिगत कुशनिंग कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन मूल समस्या बनी रहती है कि भारत की आर्थिक मशीनरी अब भी अस्थिर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की गिरफ्त में हैं, जहाँ भारी उतार-चढ़ाव है।

इज़राइल-ईरान संघर्ष ने भले ही भारत के हितों को सीधे निशाना नहीं बनाया हो, लेकिन इसके आर्थिक झटके पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। जब तक वैश्विक कूटनीति आगे बढ़कर तनाव को नियंत्रित नहीं करती, भारत का एक बार फिर बाहरी तेल संकट से जूझना पड़ सकता है, वो भी ऐसे समय में जब वह अपनी वृद्धि की गति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई बल्कि यह वास्तविक समय में घट रही है।

नाबालिग का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर बुलाया था और फिर वह उसे ट्रेन में बैठाकर अहमदाबाद ले गया। जहां उसे एक कमरे में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं, बाद में पुलिस और उसके परिजन आकर उसे ले आये। दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके और पीड़ित पक्ष के बीच रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद था। ऐसे में द्वेषता के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908